हॉस्टल के। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तुलना होनी चाहिए, सर, कि गवर्नमेंट हॉस्टल में क्या मिलता है, किस तरह की उनको ऐजुकेशन मिलती है ...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, आपका सवाल क्या है?

कुमारी मैबल रिबैलो: इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं यही पूछ रही हूं, सर। ...(**व्यवधान**)... ये इंस्टीगेट कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है क्या? ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, इस इंस्टीगेशन के बारे में होम मिनिस्टर का क्या बोलना है? ...(**व्यवधान**)...बी.जे.पी. को इसका लाइसैंस है क्या? ...(**व्यवधान**)... सर, बी.जे.पी. को इसका लाइसैंस है क्या? ...(**व्यवधान**)... बच्चों को बहकाकर, थाने ले जाकर वहां एफ.आई.आर. लॉज कराने का लाइसैंस इनको किसने दिया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सर।...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है क्या? ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है, आप सुन ही नहीं रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, यह सप्लीमेंटरी .....

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। मिस रिबैलो, आपका सवाल मुख्तसर में क्या है?

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मेरा सवाल यह है कि बी.जे.पी. को लाइसैंस है क्या कि वह बच्चों को बहकाकर, थाने में ले जाकर वहां एफ.आई.आर. लॉज कराए और उनको यह लाइसैंस किसने दिया है?

MR. CHAIRMAN: This is not a question. (*Interruptions)* This is not a question. We now go to the next Question No. 83.

Industrial Production for Mining

*83. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' Will the Minister of MINES AND MINERALS be pleased to state:

(a) whether the latest estimates on industrial production for mining has registered nil growth during 1998-99;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps initiated for attaining the estimated rate in this year; and

(d) what is the projected growth rate in this regard for the year 1999-2000?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES AND MINERALS (DR. SHRIMATI RITA VERMA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the estimate of the Index of Industrial Production (IIP) for December 1999, the growth of the mining sector was (—) 1.7% for 1998-99, and nil for the period April 1999—December 1999.

(b) The negative growth during 1998-99 was mainly due to fall in production of fuel minerals i.e. coal, lignite, petroleum (crude) and minerals like chromite, copper ore, gold, iron ore, manganese ore, limestone, magnesite and mica. The reasons for shortfall in production for petroleum (crude) were decline in production from matured fields, geological surprise, unsuspected increase in water cut in Bombay High reservoir and continued environmental problem in eastern region. The reasons for shortfall in production of coal/ lignite were less off-take of coal by major consumers like power and cement sectors, and the reasons for shortfall in production of metallic and non-metallic minerals were operational constraints like break down of mining machinery, suspension of operation in mines, breakdown of power, as well as low demand for some minerals like chromite, iron ore, magnesite and manganese ore, limestone and mica.

(c) and (d) Production of minerals are determined by the prevailing market scenario and consequently, it may not be possible to lay down definite targets of production for non fuel minerals. However, the Government has taken long term measures for development of the mines and mineral sector. The National Mineral Policy, 1993 for the non fuel sector was framed. The Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 was amended in 1994 and recently in December, 1999 in order to make the mining sector more investor friendly and progressive. The recent amendments have introduced the stage of reconnaissance operations in line with global practice, delegated more powers to the State Governments for grant, renewal and transfer of mining leases for cutting down procedural delay, empowered the States to prevent and take action against illegal mining etc.

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह कहा गया है कि यह जो खनन है, यह अप्रैल 1999 से दिसंबर, 1999 की अवधि में शून्य रहा है और इसके पहले खनन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। महोदय, मेरे पास रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए जो

आंकड़े हैं, उनसे यह पता चलता है कि खनन क्षेत्र में गिरावट आई है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसकी जो भागीदारी रही है, उसका जो हिस्सा रहा है, उसमें बहुत गिरावट आई है। पहले जहां उसकी भागीदारी 15.6 प्रतिशत थी, वह घटकर अब केवल 4 प्रतिशत रह गई है। मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि खनन स्थिति सुधारने के लिए, उससे संबंधित कानूनों में 1993 से अब तक चार बार संशोधन किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद खनन की प्रक्रिया बढ़ नहीं रही है, बल्कि उसमें गिरावट आती जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इसका मूल कारण क्या है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है।

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इंडेक्स ऑफ इंडिस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, खनन संबंधी क्षेत्र इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन है। यदि आप एक हजार के स्केल पर देखें तो खनन क्षेत्र की सहभागिता सिर्फ 104.73 है। इसका एक बड़ा शेयर मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में है जो कि 793.58 है और दूसरा है विद्युत ऊर्जा का क्षेत्र जो 101.69 है। इसीलिए खनन क्षेत्र का शेयर बहुत ही कम है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह जो 90 का दशक रहा है, यह खनन क्षेत्र के लिए बहुत सुखद और आशाजनक नहीं रहा है। इस दशक में खनन क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उतार-चढ़ाव आए हैं और बड़ी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि चढ़ाव बहुत कम और उतार बहुत ज्यादा आए हैं। इसके कई कारण हैं। खनन क्षेत्र का जो हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा प्रपोर्शन ईंधन खनिजों का है और 85 प्रतिशत से ज्यादा ईंधन खनिज है जैसे कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम। वर्ष 1998-99 में इन ईंधन खनिजों के उठाव में बहुत कमी आई है, इसलिए उनका उत्पादन भी कम हुआ है। कोयला और लिग्नाइट में उपभोक्ताओं के द्वारा उठाव कम होने के कारण इनका उत्पादन कम करना पड़ा क्योंकि इनको बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता। पेट्रोलियम के सैक्टर में गैस के उत्पादन में वृद्धि ज्यादा हुई है लेकिन क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। उसके कई कारण हैं। बंबई हाई, जो कि ऑयल फील्ड है, वह बहुत मैच्योर कर गया है और धीरे-धीरे उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है। इसके अलावा रिज़र्वायर मैनेजमेंट प्रॉबल्मस हैं। इसके अलावा उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या है।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ जो नॉन-फ्युअल मिनरल्स हैं जैसे क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड , ऑयरन-ओर मैंगनीज़-ओर, माईका, लाईमस्टोन, मैग्नेसाइट - इन सबमें खनन संबंधी दिक्कतों और बाज़ार में माल का उठाव न होने के कारण इनके उत्पादन में कमी आई है।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': सभापति जी, माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में यह भी

कहा है कि खनन मशीनों में खराबी और खानों में प्रचलनों के स्थगन और बिजली फेल होने के कारण खनन की प्रक्रिया बाधित हुई है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए विभागीय स्तर पर क्या किया जा रहा है और इसके संबंध में मंत्री जी कुछ जानकारी देंगी क्या?

डॉ (श्रीमती) रीता वर्मा: सभापति जी, सरकार इसके लिए उपाय कर रही है। मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगी कि खनन क्षेत्र में जेस्टेशन पीरिएड बहुत लम्बा होता है। हम जो उपाय कर रहे हैं, उनका असर प्रत्यक्ष रूप से देखने में 4-5 साल या उससे कुछ ज्यादा समय लग सकता है। हमने जो उपाय किए हैं, वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगी। जो नॉन फ्युअल और नॉन आटोमिक मिनरल्स हैं, उनके लिए, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने बताया कि चार बार सुधार हो चुका है। हमारी सरकार ने माइन एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवपलमैंट एक्ट को 1999 में अमेंड किया जिससे कि खनन क्षेत्र में मूलभूत सुधार किया जा सके और हम इसको ज्यादा से ज्यादा पूंजी-निवेश के उपयुक्त बना सकें। पूंजी-निवेश के बाद जो निवेशकर्ता हैं, उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसीलिए यह अमेंडमैंट किया गया है। वर्ष 1999 का जो अमेंडमैंट है, जैसे कि पूरे विश्व की प्रचलित पद्धति है उस तरीके के रिक्वानाइजा आपरेशन के लिए व्यवस्था की गई है। उसमें राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, उनको माइनिंग लीज ग्रांट करने, उसके रेन्युअल का और उसके ट्रांसफर सभी का अधिकार उनको दिया गया है। इस तरह से राज्यों के अधिकारों को और भी विकसित और सुदृढ़ किया गया है ताकि वह खनन क्षेत्र का विकास कर सकें और गैर-कानूनी खनन के विरुद्ध भी उपाय कर सकें।

जहां तक कोयला लिग्नाइट की बात है हम लोग इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। नयी खानों का चयन किया गया है और उनको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगी कि कोयला क्षेत्र में हमारा जो बल्क कंज्युमर है वह पावर सैक्टर है। उसके पास वर्ष 1998-99 में कोयला का स्टॉक काफी ज्यादा था इसलिए उन्होंने कोयले का उठाव बहुत कम किया था। अब उनका स्टॉक बहुत कम हो गया है इसलिए उनके उठाव में काफी वृद्धि हुई है। मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूंगी। वर्ष 1994-95 में कोयले का कुल उत्पादन 253.73 मिलियन टन था, वर्ष 1995-96 में 270.12 मिलियन टन था, वर्ष 1996-97 में 285.63 मिलियन टन था यानि यह हर साल बढ़ता गया है। यह वर्ष 1997-98 में 295.80 मिलियन टन था और वर्ष 1998-99 में थोड़ा कम हो कर 292.70 मिलियन टन हुआ। लेकिन इस साल हम अभी अपने टारगेट के अनुसार चल रहे हैं और दिसम्बर माह तक 208.18 मिलियन टन प्रोडयूस कर चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम 298.90 मिलियन टन उत्पादन कर सकेंगे।

SHRI PREM CHAMD GUPTA: Sir, the lady Minister has done a good homework. But, it seems, she has not been briefed properly. In her reply, she

has stated that the lifting was not enough and that was the reason why the production was low. It is not correct. You would know that a large quanity of coal is being imported. If there was not lifting, why did the import take place?

The second point is, coming to the mineral side, like gold, copper; India is the largest importer of these two minerals in the world. So, if we were the largest importer, we had consumption; and if we had consumption, there was no reason for reduction in prodcution. It is not the lifting problem. The problem is something else. The problem is, our technology in mining sector has become obsolete. The Government policies are not favourable for investment, modernisation, and they are also not lucrative for the States. So, the first part of my supplementary is, if there was no lifting, why were the imports allowed? The second part of my supplementary is, what the Government intends to do to avoid such a situation in future?

DR. (SHRIMATI) RITA VERMA: Sir, as far as the first question is concerned, I think, it is beyond the jurisdiction of my Ministry. Maybe, his question should be directed to the Finance Minister. *(Interruptions)*

SHRI PREM CHAND GUPTA: I am sorry, Import is not under the Finance Ministry. It is under the Commerce Ministry. But, Madam, yours is a nodal Ministry. You should have represented, your Ministry should have represented to the Commerce Ministry, that mines are becoming sick because there is no lifting. Sir, the Eastern Coalfields is a sick company today, and it is registered with the BIFR also. So, I am sorry...(*Interruptions*)

DR. (SHRIMATI) RITA VERMA: Sir, we are taking a numbers of steps for improving the productivity of our coal mines and for the redressal of the grievances of our consumers. The steps taken by Coal India Limited for meeting the coal requirement of power projects in the country during the Ninth Plan, in general, and the Western region, in particular, are given below: Opening up of new mines and increasing the efficiency and productivity of the existing mines by modernisation, application of new technology and ensuring timely availability of inputs and infrastructural facilities; partial deregulation of coal prices, which is likely to improve the generation of internal financial resources of the coal companies. It will facilitate implementation of projects. It will also improve the financial viability of new mining projects. (*Interruptions*) Yes; what do you want? Sir, I would like to reassure the hon. Member that during the current year, the coal production target of 298.90 million tonnes is likely to be fully achieved. A positive growth is already

evident. During the period April—December, 1999 the production has been more than 208 million tonnes, and the offtake has also improved, registering a growth of about 4 per cent so far. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No nothing. It's allright. Now Shrimati Kamla Sinha.

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति, महोदय, मंत्री महोदया ने काफी तैयारी के साथ जबाब दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। इन्होंने अपने जवाब में कहा कि कोल का मेजर कंज्यूमर पॉवर और सीमेंट सैक्टर है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सही है कि सीमेंट इंडस्ट्री में कोयला रॉ मैटीरियल की तरह चलता है। आज पूरे देश में सीमेंट इंडस्ट्री में स्लम है। कोयले की शॉर्ट फॉल के कारण यह हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि एक तो जो प्रेमचन्द गुप्ता जी ने कहा कि बाहर से कोयला आयात किया जा रहा है और दूसरी तरफ पॉवर सैक्टर में कोयला समय पर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हमेशा पॉवर फेलियर होता रहता है, पॉवर हाउसेस बंद रहते हैं। जिस स्टेट से वह खुद आती हैं, उस स्टेट को भी यही हालत है। क्या मंत्री जी इन मामलों का सुधार करेंगी, यह मैं जानना चाहती हूं।

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा: मैं माननीय सदस्य को यह एश्योर करना चांहूगी कि इसके सुधार के लिए मैं पूरा-पूरा प्रयत्न करूंगी।

श्रीमती कमला सिन्हा: कैसे करेंगी, वह बता दीजिए।

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा: नयी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अब उठाव बढ़ रहा है।

श्रीमती कमला सिन्हा: कोयले की लिफ्टिंग के लिए रेलवे मिनिस्टरी से आपको पता करना पड़ेगा।

Your Ministry is the nodal ministry. You will have to consult the Railway Ministry. दोनों का ज्वाइंट वैंचर होना चाहिए तभी यह संभव हो सकेगा।

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा: मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगी कि रेलवे वैगन की अवेलेबिलिटी में कोई प्राब्लम नहीं है। इसमें प्राब्लम के दो पहलू थे। एक तो पहले चूंकि उधार में हम बहुत कोयला देते थे इसलिए कोयले का उठाव ज्यादा था लेकिन जब हमको सेल रियलाइज़ेशन में प्राब्लम होने लगी तो हमने कैश एंड कैरी सिस्टम शुरू कर दिया। अब जितना पैसा पावर सैक्टर से जमा होता है, हम उसी के अगेंस्ट कोयला देते हैं। इससे उसका उठाव कम हो गया। उन्होंने, पहले जो उनका अवेलेबल स्टाक था, उसको खत्म करने की दिशा में कदम उठाए, इसलिए जितना भी कोयला उनके पास अवेलेबल था, वह खत्म हो गया है। मैंने जो कहा कि चार परसेंट अपटेक बढ़ा हुआ है, वह इसलिए कि उनके पास पहले का जो स्टाक था, वह खत्म हो गया

है। कानूनन जो पिटहैड थर्मल पावर प्लांट हैं, उनके पास 15 दिनों का ईंधन रहना चाहिए और जो पिटहैड से दूर हैं उनके पास 30 दिनों का ईंधन रहना चाहिए। उनको अगर दिक्कत होती है तो हमने उनको क्रेडिट फैसेलिटी भी दी है ताकि कोयले का उठाव बढ़ सके। मैं माननीय सदस्या की चिंता से पूरी तरह सहमत हूं कि सीमेंट इन्डस्ट्री में बहुत ज्यादा रिसैशन आ गया है। लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि अब जबकि इनफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ज्यादा ज़ोर दे रही है, मुझे विश्वास है कि सीमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके साथ हमारा कोयले का उठाव भी बढ़ेगा।

SHRI JIBON ROY: Sir, the hon. Minister is making her maiden reply. The thing is that, in all these areas like, coal, lignite, petroleum, chromite, copper, iron-ore, manganese, limestone, magnesium, mica etc., there is a decline. Sir, the production even in the manganese queries has gone down below the level of 1993-94, which is the base year. The reply of the hon. Minister is not correct. You are importing coal. But the best quality coking coal is within our reach. But the thing is that, your are not digging it out. I agree that Bombay High Crude is getting exhausted in the shore areas, but in the deep sea, there is sufficient crude. It is not being exploited. Sir, the Government has changed the mineral law, lock, stock and barrel. It has opened up the sector to foreign companies, private companies, with the expectation that money will come from outside. There was no public investment during the last 6-7 years. Now, we are importing everything. Our mines are being closed. I personally know this thing because I move around all these mines. I take care of the trade union activities in these areas. Sir, it is a serious situation. It is now proved that the mining and mineral policy of the Government has collapsed. There should be sufficient public investment in these areas, and technology upgrdation should also be there. Now, I would like to know whether the Government is going to change its policy in this regard. Sir, at the same time, I would request you to have a half-an- hour discussion on this matter because it is a very serious matter.

MR. CHAIRMAN: You give notice for that.

DR. (SHRIMATI) RITA VERMA: Sir, as far as opening of new mines and the development of the existing mines is concerned, we need massive investment. This is the crux of the problem. In order to attract investment in the coal sector, the Government is proposing to bring in a legislation under which any Indian company, public sector or private sector, would be in a position to do coal mining, without the restriction of captive use. Such investor-friendly move will give a boost to the production and availability of

indigenous coal. Sir, with regard to his question about the petroleum sector, I would adivse him to address that question to the Minister of Petroleum.

MR. CHAIRMAN: We have spent enough time on this question. Now, Question No. 84.

Harassment of Innocent people while dealing with Militants

*84. SHRI SHARIEF-UD-DIN SHARIQ: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what steps have been taken to stop the crossing of LoC by the militants in J&K and the result thereof;

(b) whether different security agencies have given different number of militants present in the State;

(c) what is the actual number who have crossed the LoC after Kargil incident;

(d) whether there is any direction to the security forces, that while dealing with militants, innocent citizens should not be harassed; and

(e) if so, the reasons for which the reports of harassment of innocent people are coming regularly?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Appropriate measures continue to be taken against infiltration by terrorists. Following are some of such measures:—

(a) The army has been deployed in direct eyeball to eyeball attack with adversary's troops.

(b) All routes of ingress and infiltration are guarded any patrolled by our troops.

(c) Adequate defensive and counter-infiltration postures have been adopted in dynamic tiers.

(d) Retaliatory fire is brought down upon the Pakistani troops in the event of unprovoked firing by Pakistan, that is often taken recourse to, to provide cover to infiltration attempts.